हिन्दी दैनिक

इंडिया वार्ता

R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104

सच के साथ-जन के साथ

लोकतंत्र में जनसरोकार का सशक्त माध्यम

वर्ष : 14 अंक : 302 | देहरादून,गुरूवार 03 जुलाई 2025 | शुल्क : पचास पैसे | पृष्ठ संख्या : 08

आत्मिक वाणी

मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना अपने मन मे मेरी बातों को याद रखना क्योकि ऐसा करने से तेरे जीवन के दिन और तेरे वर्ष और बढ़ेगे। तेरा अधिकाधिक कल्याण ही होगा मेरे पुत्र करूणा और सच्चाई कभी तुझ से अलग ना हो तू उनको अपने गले का हार बना कर रखना और उनकों अपने हृदय पटल पर लिख लेना तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में कृपा का पात्र होगा।

सूबे के नर्सिंग कॉलेजों में पूर्व की .. 8

26 किमी रिस्पना - बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र से अनुरोध:सीएम

पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फ्लोटिंग पापुलेशन हेतु सुविधाओं की व्यवस्था के लिए नीति आयोग से विशेष ग्रांट का आग्रह

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू हो जाने पर राज्य में भारी संख्या में पर्यटकों की आने संभावना को देखते हुए राज्य सरकार नियोजन की चुनौती पर अभी से पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है 7 उन्होंने कहा कि शहर की ट्रैफिक समस्या और भविष्य की जरूरत को देखते हुए 26 किमी रिस्पना - बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है7 सीएम ने बताया कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फ्लोटिंग पापुलेशन हेतु सुविधाओं की व्यवस्था के लिए नीति आयोग से विशेष ग्रांट का आग्रह किया गया है 7 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है 7 हम एसडीजी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहे7 जीईपी लागू करने वाले सबसे पहले राज्य बने 7 यूसीसी लागू करने वाले भी सबसे पहले साहसी राज्य बने7 हम अपनी 6500 एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवा चुके हैं 7 राज्य में निरंतर विकास के नवाचार अपनाए जा रहे हैं7

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में फोटोग्राफर श्री भूमेश भारती की कॉफी टेबल बुक एरियल विस्टाज़ ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया 7

कार्यक्रम में उपस्थित छायाचित्रकारों, कला एवं प्रकृति प्रेमियों सहित उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भूमेश भारती जी ने 15 वर्षों की अथक साधना, समर्पण और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ उत्तराखंड की प्रकृति और संस्कृति

- शेष पृष्ठ 7 पर ...

उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश संपत्ति विवाद : धामी सरकार ने तेजी लाने के दिए निर्देश, जल्द होगी CM योगी संग बैठक

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विभाजन के बाद से लंबित पड़े परिसंपत्तियों और देनदारियों के मामलों को सुलझाने की दिशा में धामी सरकार ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में इस संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को इन मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उन मामलों पर जोर दिया जिनमें पिछली द्विपक्षीय बैठकों में दोनों राज्यों के बीच सहमति बन चुकी थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री श्री पुष् पुष्कर सिंह धामी स्वयं जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

पिछली मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद से कुछ प्रगति भी हुई है। इनमें जिला उधमसिंहनगर और हरिद्वार में स्थित जलाशयों/नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति मिलना शामिल है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखंड को विद्युत बिलों के रूप में 57.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम ने भी उत्तराखंड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को 3.98 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। वन विकास निगम उत्तराखंड को देयताओं का आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है, जबकि परिवहन निगम की अवशेष राशि का भुगतान भी हो चुका है। आवास विभाग के अंतर्गत आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों के निस्तारण का निर्णय भी लिया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. नीरज खेरवाल और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड सरकार इन दशकों पुराने लंबित मामलों को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और विकास की राह प्रशस्त हो सके।

पाकिस्तान को 182 देशों का समर्थन मोदी सरकार की विफलता : माहरा

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में हुए हालिया मतदान में पाकिस्तान को 193 में से 182 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। यह केवल पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक साख को लगी एक गहरी चोट है। यह मोदी सरकार की तथाकथित सशक्त विदेश नीति और झूठे प्रचारतंत्र की पूरी तरह से पोल खोलता है। मीडिया को जारी एक बयान में माहरा ने कहा कि बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई भारी-भरकम विदेश यात्राएं, करोड़ों रुपये की पीआर रणनीतियां और विश्वगुरु की मिथ्या छवि, सब कुछ आज ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से रिश्ते संभाल नहीं पाए। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अब मालदीव तक भारत से दूर हो चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की निष्क्रियता और अवसर चूकने की आदत के चलते, भारत सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। उन्होंने कहा कि संघर्षविराम की कमजोर और बिना सोच-समझ की नीतियां आज भारत को वैश्विक अलगाव की ओर धकेल रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भारत सरकार इस अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी पर देश को तत्काल स्पष्टिकरण दे। विदेश नीति की विफलता को लेकर संसद में विस्तृत बहस कराई जाए। प्रधानमंत्री स्वयं देश को बताएं कि कैसे उनकी ब्रांड मोदी विदेश नीति ने भारत को अलग-थलग कर दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत की आवाज कमजोर पड़ती जा रही है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भाजपा की खोखली विदेश नीति, और झूठ पर आधारित प्रचार तंत्र है।

सीएम ने सड़क दुघर्टना में मृत कांवड़ यात्रियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जनपद में खाड़ी के पास हुई सड़क दुघर्टना में मृत कांवड़ यात्रियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

जिलाधिकारी टिहरी ने बताया कि बुधवार सुबह कांवड़ यात्रियों का एक ट्रक खाड़ी से दो किमी आगे पलट गया था। जिसमें 18 यात्री सवार थे, उन्होने बताया कि दुर्घटना में तीन कांवड यात्रियों की दु:खद मृत्यु हुई है। दुर्घटना के बाद प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान संचालित करते हुए, सभी यात्रियों को ट्रक से बाहर निकाला। जिसमें से चार घायलों को एम्स ऋषिकेश और शेष को नरेंद्र नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक को सीधा कर लिया गया है।

सम्पादकीय

'महिला'

यह श्लोक हजारों वर्ष पहले हमारे भारत में उस समय लिखा गया था जब हमारे पूर्वज नारी की शक्ति से अच्छी तरह परिचित थे। 'महिला' से आशय सिर्फ स्त्री लिंग नहीं है, बल्कि इसका अर्थ इससे भी कहीं आगे है। महिलाएं समाज का आधा हिस्सा हैं और वे परिवार की रीढ़ होती हैं। जहां महिलाओं का सम्मान होता है और उन्हें सही दर्जा मिलता है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले के दिनों के उलट, सदियों से विभिन्न कारणों से हमारी महिलाओं को घरों के भीतर रखा गया। प्राचीन भारत में, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर माना जाता था और उन्हें बौद्धिक बहसों, प्रशासन, संपत्ति उत्तराधिकार, विद्वतापूर्ण ज्ञान आदि के मामले में मौके दिए जाते थे। बाद में महिलाओं को शिक्षा, सामाजिक स्थिति और काफी हद तक उनके अस्तित्व से वंचित कर दिया गया। उनकी पहचान केवल एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में या एक मां के रूप में ही सिमट गई और उन्हें समानता एवं साहस के गौरव से वंचित हो जाना पड़ा। मुझे लगता है कि महिलाएं पेड़ से बंधी मादा हाथी की तरह होती हैं। एक मादा हाथी के लिए एक पेड़ को उखाड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, और वह उसे आसानी से खींच सकती है। लेकिन मादा हाथी सोचती है कि वह जंजीर से बंधी है और इसलिए वह अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करती है। महिलाओं के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। वे कुशल प्रबंधक होती हैं, परिवार की नींव होती हैं, बेहद मेहनती होती हैं; लेकिन वे इस मानसिकता में जकड़ी होती हैं कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकतीं या अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकतीं। इस तरह से सोचना संभव है क्योंकि किसी भी हलचल या लहर को प्रेरित करने के लिए एक प्रस्थान बिंदु की जरूरत होती है। यह बिंदु मिलेगा कैसे? कौन उनकी मदद करेगा? कौन उन्हें विश्वास दिलाएगा? कौन उनकी मदद करने के लिए नीति प्रदान करेगा या कौन पहली बार उसकी क्षमता को सामने लाएगा? धुएं से भरे रसोईघर से उसका बाहर आना कौन स्वीकार करेगा? एक नया उद्यम शुरू करने की इच्छा जताने पर कौन उसकी मदद करेगा? कौन खेल, स्वास्थ्य, रक्षा और विमानन के क्षेत्र में उसकी क्षमता की सराहना करेगा? एकबारगी यह सब हो जाए, तो वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भरपूर क्षमता के साथ खुद को आगे बढ़ाएगी। उनके जीवन में इस तरह का अदभुत बदलाव एक ऐसे सही नेता की वजह से संभव हुआ है, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को लेकर बात की और लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि बेटियां ईश्वर का अनमोल उपहार हैं। उक्त नेता ने इस देश के सभी आम पुरुषों व महिलाओं के साथ अच्छे जीवंत और वास्तविक उदाहरणों के साथ एक कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत शुरू की।

महिला आरक्षण की दहलीज़ पर लोकतंत्र: अब दलों को जिम्मेदारी उठानी होगी

---प्रियंका सौरभ

2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में राजनीति के स्वरूप को बदलने का ऐतिहासिक अवसर है। हालांकि इसका क्रियान्वयन 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संभव है, लेकिन यह तभी सफल होगा जब राजनीतिक दल अभी से महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाएँ। केवल आरक्षित सीटें देना पर्याप्त नहीं; दलों को आंतरिक कोटा, वित्तीय सहयोग, प्रशिक्षण, मेंटरशिप और निर्णयकारी भूमिका में महिलाओं को प्राथमिकता देनी होगी। अगर यह मौका चूक गया तो आरक्षण भी दिखावा बन जाएगा। समावेशी और सशक्त लोकतंत्र के लिए अब निर्णायक और नीतिगत पहल ज़रूरी है। 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी संविधान का 106वां संशोधन, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का ऐतिहासिक प्रयास है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है, लेकिन इसकी सफलता महज संविधान में दर्ज होने से नहीं होगी—बल्कि इस पर अमल करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति से तय होगी। वर्ष 2029 के आम चुनावों में यदि यह आरक्षण प्रभावी होता है, तो यह न केवल भारत के लोकतंत्र के लिए निर्णायक मोड़ होगा, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व की दिशा भी तय करेगा। इसके लिए राजनीतिक दलों को अभी से व्यापक और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे। भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति हमेशा सीमित रही है। 2024 में चुनी गई 18वीं लोकसभा में सिर्फ 74 महिलाएं चुनकर आईं, जो कुल सीटों का मात्र 13.6त्न हैं। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में भी घटा है और वैश्विक औसत 26.9त्न से काफी पीछे है। राज्य विधानसभाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां औसतन केवल 9त्न ही महिलाएं विधायक हैं। यह न केवल लैंगिक असमानता को दर्शाता है बल्कि नीति-निर्धारण की उस प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है जिसमें आधी आबादी की हिस्सेदारी नगण्य है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के निम्न स्तर के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है भारतीय समाज की गहरी पैठी हुई पितृसत्तात्मक सोच। महिलाओं को पारिवारिक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे नेतृत्व के अवसर स्वाभाविक रूप से पुरुषों को मिलते हैं। सरपंच पति जैसी प्रथाएँ इस सोच को और भी स्पष्ट करती हैं।

राजनीतिक दलों के भीतर भी यह धारणा प्रचलित है कि महिलाएं चुनाव जीतने की दृष्टि से कमज़ोर प्रत्याशी होती हैं। लेकिन यह एक मिथक है, जिसे हाल के आंकड़े खारिज करते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाएं केवल 9.6% उम्मीदवार थीं, लेकिन उनकी सफलता दर पुरुषों से अधिक थी - उन्होंने 13.6त्न सीटें जीतीं। महिलाओं के सामने आर्थिक संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा है। भारत में चुनाव लड़ना अत्यंत महंगा है, और अधिकांश महिलाएं—खासकर ग्रामीण व पिछड़े वर्गों से—स्वतंत्र रूप से इतने संसाधन नहीं जुटा सकतीं। इसके अलावा, राजनीति का वातावरण भी महिलाओं के लिए असुरक्षित और शत्रुतापूर्ण रहता है। उन्हें ट्रोलिंग, चरित्र हनन, और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास डगमगाता है।

राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षित नेतृत्व विकास, और निर्णय लेने वाली इकाइयों में शामिल करने जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ भी अक्सर अनुपस्थित रहती हैं। महिला मोर्चा बनाकर उन्हें पार्टी के मुख्य ढांचे से अलग कर दिया जाता है, जिससे वे सत्ता के निर्णायक केंद्रों से दूर रह जाती हैं। 2029 के आरक्षण को सार्थक बनाने के लिए राजनीतिक दलों को अब से ही तैयारी करनी होगी। सबसे पहला कदम है—स्वैच्छिक आंतरिक कोटा। टिकट वितरण में 33% महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना केवल आरक्षण की तैयारी नहीं, बल्कि समावेशी लोकतंत्र की दिशा में पहल होगी। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी जैसी मिसालें बताती हैं कि आंतरिक कोटा राजनीति की संस्कृति को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। दूसरा आवश्यक कदम है—वित्तीय सहायता और संरचित प्रशिक्षण। राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवारों के लिए अलग चुनावी फंड बनाना चाहिए ताकि वे चुनावी खर्च का बोझ उठा सकें। कनाडा का जूडी लामार्श फंड इसका अच्छा उदाहरण है। साथ ही, पंचायतों और नगरपालिकाओं में सक्रिय महिला प्रतिनिधियों को विधानसभा और संसद स्तर के लिए तैयार करने का नेतृत्व कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए।

महिलाओं को पार्टी की कोर कमेटियों, नीति निर्माण इकाइयों और प्रवक्ता मंडल में भी सक्रिय भूमिका देनी चाहिए। केवल महिला मोर्चा या सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित रखकर नेतृत्व नहीं उभरेगा। IUML जैसी पार्टियों ने हाल ही में कोर नेतृत्व में महिलाओं को शामिल किया है—अन्य दलों को भी यही दिशा लेनी चाहिए। मेंटोरशिप भी एक सशक्त उपकरण हो सकता है। अनुभवी महिला नेता अगर नवोदित उम्मीदवारों को मार्गदर्शन दें, तो आत्मविश्वास, नीति की समझ, और रणनीतिक कौशल विकसित हो सकता है। इसके साथ ही, पार्टी के भीतर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न या असम्मानजनक व्यवहार को रोकने के लिए सख्त आचार संहिता और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था ज़रूरी है।

राजनीतिक दलों के प्रयासों के साथ-साथ मीडिया और नागरिक समाज की भी भूमिका अहम है। मीडिया को महिला नेताओं की नीतिगत भूमिका, वैचारिक दृष्टिकोण और सामाजिक योगदान पर केंद्रित करना चाहिए—ना कि उनके पहनावे, निजी जीवन या विवादों पर। नागरिक संगठनों को भी प्रशिक्षण, जनजागरण और महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल करनी चाहिए।

महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व केवल लैंगिक समानता का सवाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी मापदंड है। यदि प्रतिनिधित्व का आधार केवल पुरुषों की पहुंच और दबदबे तक सीमित रहेगा, तो लोकतंत्र का स्वरूप अधूरा ही रहेगा। महिला आरक्षण केवल एक नीति नहीं, बल्कि नेतृत्व को समावेशी, संवेदनशील और संतुलित बनाने का औजार है। 2029 का चुनाव भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आएगा। लेकिन यदि राजनीतिक दल अभी से महिला नेतृत्व को गढ़ने में निवेश नहीं करते—तो यह आरक्षण भी केवल सत्ता में वंशवाद और प्रतीकात्मकता का विस्तार बनकर रह जाएगा। अब वक्त है कि दल औरतों के लिए सीट छोड़ने की बात नहीं करें, बल्कि औरतों को नेतृत्व के लिए खड़ा करने की पहल करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने का यही असली रास्ता है।

जिम्मेदार कौन ?

प्रिय पाठकों आप भी एक पत्रकार हो तथा **दैनिक इंडिया वार्ता** की आवाज बन सकते हैं। बस आपको इसके लिए जरूरत है कि हर समय अपनी आंख व कान खुली रखें। चौंकन्ने रहें कि आपके चारों ओर क्या कुछ घटित हो रहा है। नाबालिग बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं? स्कूल बंक कर रहे हैं? विकास कार्यों में गड़बडी हो रही है? निर्माण कार्य महीनों से अधूरे पड़े हैं, पाइप लाइन टूटी हैं, घरों में दूषित पेयजल आपूर्ति या महिनों से पानी नहीं आ रहा है। मनरेगा में धांधली हो रही है? आपकी इस प्रकार की समस्याओं को **दैनिक इंडिया वार्ता** जिम्मेदार कॉलम में प्रमुखता के साथ उठाएगा? बस आप उठाइए कलम और तुरंत लिखकर हमें भेजें या फिर संपर्क करें? आपकी आवाज को सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों एवं सम्बन्धित अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा तथा इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल कराने का प्रयास भी किया जाएगा।

संपर्क करें
संपादक
दैनिक इंडिया वार्ता

प्रधान कार्यालय : मोहक्कमपुर खुर्द पोस्ट आई.आई.पी. रेलवे क्रसिंग हरिद्वार रोड़ देहरादून (उत्तराखण्ड)
मोबाईल न.- 7500581414,9359555222
Email: indiawarta@gmail.com

डीएम बंसल ने गिफ्ट डीड को किया खारिज, पूर्ण 3080 वर्ग फीट सम्पति पुन: बुजुर्ग दम्पति के नाम की

-गिफ्ट डीड पाकर बेटे ने कर दिया था माता-पिता को सम्पति से बेदखल पोते-पोती से मिलने पर लगा दी थी रोक

-बुजुर्ग सरदार परमजीत सिंह व उनकी पत्नी अमरजीत कौर को मिला न्याय

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । जिलाधिकारी सविन बंसल के राज में जिला प्रशासन सामाजिक कर्तव्य से विमुख लोगों को अपनी न्याय प्रणाली से रास्ता दिखा रहा है वहीं असहाय जरूरतमंद लोंगों को त्वरित न्याय मिल रहा है। जिलाधिकारी सविन बसंल की कार्यप्रणाली सदैव असहाय, बुजुर्ग, महिला बच्चों, जनमानस के हित में रही है। असहाय जरूरतमंदो से जुड़े विषयों पर जिला प्रशासन द्वारा सक्रिय होकर त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। यह जनमानस के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाता है।

बजुर्ग परमजीत सिंह ने अपनी 3080 वर्ग फुट सम्पति जो कि 2 बड़े हॉल है को गिफ्ट डीड में अपने पुत्र गुरूविंदर सिंह के नाम कर दिया था। गिफ्ट डीड की शर्तो के अनुसार पुत्र को अपने माता-पिता के भरणपोषण एवं माता-पिता के साथ रहने तथा पोते-पोती को दादा-दादी से दूर नही करना था। किन्तु सम्पति नाम होते ही पुत्र ने गिफ्ट डीड में की शर्तो का उल्लंघन कर माता-पिता से दूर रहने लगा तथा पोते-पोती को भी दादा-दादी से मिलने नही दिया गया। बुजुर्ग दम्पति के प्रकरण पर जिला मजिस्टेªट न्यायालय में विधवत पर्याप्त सुनवाई की गई विपक्षी गुरूविंदर सिंह आदि को नोटिस जारी किया गया एवं विज्ञप्ति के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना प्रसारित की गई इसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत नही की गई और ना ही स्वयं उपस्थित हुए। जिस पर फैसला सुनाते हुए गिफ्ट रद्द करते हुए सम्पति को पुन: बुजुर्ग दम्पति के नाम कर दिया।

बुजुर्ग माता-पिता से गिफ्ट डीड में बंगला बिजनेस अपने नाम कर अपना ही बेटा उनको घर से बाहर खदेड़ रहा था। डीएम बंसल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए गिफ्ट डीड को एक झटके में ही खारिज करते हुए पूर्ण 3080 वर्ग फीट सम्पति पुन: बुजुर्ग दम्पति के नाम कर दिया है। गिफ्ट डीड शर्तों का उल्लंघनय नाफरमानी पर डीएम न्याय का हथोड़ा चलाते हुए गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया है। बुजुर्ग दम्पति तहसील, थाना अवर न्यायालय से थकहार डीएम न्यायालय कराया वाद पंजीकृत, पहली ही सुनवाई में बुजुर्ग को इंसाफ मिल गया है। भरणपोषण अधिनियम की विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीएम ने बुजुर्ग दम्पति को इंसाफ दिलाया है। आदेश फरमान से डीएम न्यायालय में ही दम्पति के आंसु छलक पड़े। वधिवत् स्पष्टीकरणय पर्याप्त अवसर उपरान्त, आदेशों की नाफरमानीय माता-पिता का तिरस्कार बेटे को भारी पड़ गया। डीएम के इस फैसले से बुजुर्ग सरदार परमजीत सिंह व उनकी पत्नी अमरजीत कौर को न्याय मिल गया है गिफ्ट डीड पाकर बेटे ने कर दिया था माता-पिता को सम्पति से बेदखलय पोते-पोती से मिलने पर भी रोक लगा दी थी।

मंत्री गणेश जोशी का बयान आपत्तिजनक : गरिमा

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के नाम पर दुकानदारों के लिए लाइसेंस और नाम उजागर करने की अनिवार्यता का भाजपा सरकार का निर्णय न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास भी है, जिसकी इजाजत संविधान कतई नहीं देती है यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का।

बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार बंधुओं के सम्मुख दसौनी ने यह बयान दिया ।गरिमा ने कहा कि मंत्री गणेश जोशी द्वारा दिया गया बयान कि अगर मैं गणेश जोशी हूं तो गणेश खान थोड़ी लिखूंगा - सीधे तौर पर एक सांप्रदायिक बयान है जिसमें खासतौर पर वर्ग विशेष को निशाना बनाया गया है जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए ।दसौनी ने कहा कि भाजपा के मंत्री जिस भाषा और मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वह संविधान और उत्तराखंड की गंगा-जमुनी तहज़ीब के खिलाफ है। यह वही भाजपा है जो हर चुनाव से पहले सबका साथ, सबका विकास की बात करती है और सत्ता में आते ही नाम और खान के आधार पर जनता को बांटने लगती है। गरिमा ने कहा की गणेश जोशी ने खाने में थूकने वाले प्रकरण का उदाहरण दिया तो ऐसे में जोशी बताएं कि यदि खाने में थूकना अपराध है तो उनके विभाग में जो चल रहा है वह किस श्रेणी में आता है? दसोनी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने बड़े विश्वास के साथ जोशी को एक नहीं कई बार विधायक चुना लेकिन आज आय से अधिक संपत्ति मामले में जोशी के ऊपर विजिलेंस की तलवार लटक रही है, वहीं उद्यान घोटाले में करोड़ों की बंदर बांट हुई है यह सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है तो ऐसे में जोशी बताएं कि वह कौनसे पाक साफ है और उन्होंने क्यों अपनी जन्मभूमि और अपने ही प्रदेश के लोगों के साथ छल कपट किया?

दसौनी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है, न कि धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को चिन्हित करना।

थूकने की वारदातों के नाम पर पूरे समुदाय को संदेह के घेरे में लाना न केवल ग़लत है, बल्कि समाज में अविश्वास और भय पैदा करने की साज़िश है। गरिमा ने यह भी कहा कि भाजपा के जिन लोगों की दुष्कर्मों में ,भ्रष्टाचार में, भर्ती घोटालो में संलिप्तता है वह भी सब अल्पसंख्यक है क्या?

गरिमा ने कहा कि भाजपा सरकार अपने विकास के विफल रिकॉर्ड को ढकने के लिए इस तरह के सांप्रदायिक बयानों और फैसलों का सहारा ले रही है।

दसौनी ने कहा कि मंत्री गणेश जोशी अपने विवादित और सांप्रदायिक बयान पर तत्काल माफी मांगें।

सरकार ने जो कांवड़ यात्रा के लिए निर्णय लिया वो नीतिगत फैसला है उसको समाज में नफरत फैलाने का राज्य का सौहार्द बिगाड़ने का हथियार न बनाया जाय।

गरिमा ने राज्य सरकार से भी अपेक्षा करी कि कांवड़ यात्रा को धार्मिक श्रद्धा का विषय रहने दें, उसे राजनीतिक द्वेष और पहचान की साजिश में न घसीटा जाए।

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष [नाम] ने कहा है कि राज्य की मिट्टी में नफरत नहीं, भाईचारा बोया गया है - भाजपा उसे जहरीले फैसलों से न उखाड़े।

पॉली किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने शिक्षक प्रशिक्षण सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । पॉली किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने आज सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, हाथीबड़कला, देहरादून में शिक्षक प्रशिक्षण सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देहरादून, जॉली ग्रांट और ऋषिकेश शाखाओं के लगभग 250 शिक्षक एकत्रित हुए। प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञ सत्रों का संचालन दिल्ली की शिक्षक प्रशिक्षक सुश्री जोआना फर्नांडीज और देहरादून के विशेष शिक्षक प्रशिक्षक डॉ. निशाद इकबाल ने किया। सत्रों में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। पॉली किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के अध्यक्ष कैप्टन मुकुल महेंद्र द्वारा शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली और स्कूल स्वचालन पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं से लैस करना था, जिससे वे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सकें।

कारगी चौक के पास सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटने पर किया प्रदर्शन

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । देवभूमि रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने कारगी चौक के पास स्थित सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सभी ने नारेबाजी कर अपना आक्रोश प्रकट किया। मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामी बंसल को ज्ञापन सौंपकर कब्जा हटवाकर स्वामित्व का बोर्ड लगाने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कारगी चौक के पास एक निजी कंपनी के शोरूम के पास बेशकीमती सरकारी जमीन को ठिकाने लगाया जा रहा है। यहां अवैध रूप से पुश्ते का निर्माण करवाने के आरोप लगाया है। कार्यकर्ता हिन्द प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायत दर्ज करने के बावजूद सरकारी जमीन को कब्जामुक्त नहीं करवाया गया। उनका कहना है कि पूछने पर बताया कि यहां विधायक निधि से पुश्ता बन रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार और जनप्रतिनिधियों की छवि खराब हो रही है। राघव उपाध्याय ने कहा कि निगम ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन करेंगे। इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा उठान के कार्य में लापरवाही बरतने वाली कंपनी और चूना खरीद में सामने आए फर्जीवाड़े के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर भी नाराजगी जताई।

वैश्विक नेताओं से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं', पांच देशों की यात्रा पर बोले पीएम मोदी

नईदिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को घाना की राजधानी अकरा के लिए रवाना हुए। यह उनकी पांच देशों की यात्रा का पहला चरण है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के वैश्विक साझेदारी को ग्लोबल साउथ और अटलांटिक के दोनों पक्षों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा शामिल हैं। पीएम मोदी ने इन देशों को भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बताया, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और बहुपक्षीय सहयोग से जुड़े हैं।

अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर मैं 2-3 जुलाई को घाना का दौरा करूंगा। घाना ग्लोबल साउथ में एक मूल्यवान साझेदार है और अफ्रीकी संघ और पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास साझेदारी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि घाना की संसद में बोलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।

इसके बाद, पीएम मोदी 3-4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह भारत के साथ %गहरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव' साझा करता है। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू से मिलूंगा, जो इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि थीं और दूसरी बार कार्यभार संभालने वालीं प्रधानमंत्री कमला परसाद-बिसेसर से मुलाकात करूंगा।

प्रवासी समुदाय के लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 180 साल पहले भारतीय पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। यह दौरा हमारे पुश्तैनी और रिश्तेदारी के विशेष बंधनों को नया जीवन देने का अवसर देगा। पीएम मोदी पोर्ट ऑफ स्पेन से ब्यूनस आयर्स जाएंगे, जो 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का अर्जेंटीना का पहला द्विपक्षीय दौरा होगा।

अर्जेंटीना को लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार और जी20 में निकट सहयोगी बताते हुए उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं, जिनसे मैं पिछले साल भी मिला था। हम कृषि, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान देंगे।

अर्जेंटीना के बाद, पीएम मोदी 6-7 जुलाई को रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत की ब्रिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ब्रिक्स को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच मानता है। हम मिलकर एक अधिक शांतिपूर्ण, समान, न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयास करते हैं।

उन्होंने पुष्टि की है कि वह शिखर सम्मेलन के दौरान कई विश्व नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। ब्राजील की यात्रा ब्रासीलिया में एक द्विपक्षीय राजकीय दौरे के साथ जारी रहेगी, जो लगभग छह दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। उन्होंने कहा, यह दौरा ब्राजील के साथ हमारी निकट साझेदारी को मजबूत करने और मेरे मित्र राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर देगा।

पीएम मोदी की यात्रा का अंतिम पड़ाव नामीबिया होगा, जिसे उन्होंने एक भरोसेमंद साझेदार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि वह राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवा से मुलाकात और हमारे लोगों, हमारे क्षेत्रों और व्यापक ग्लोबल साउथ के लाभ के लिए सहयोग का एक नया रोडमैप तैयार करने के लिए उत्सुक हैं। वह नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी ने अपनी बहु-देशीय यात्रा के परिणामों के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि पांच देशों की मेरी यात्राएं ग्लोबल साउथ में हमारी दोस्ती के बंधनों को मजबूत करेंगी, अटलांटिक के दोनों पक्षों पर हमारी साझेदारी को और गहरा करेंगी और ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरीकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों में हमारी भागीदारी को बढ़ाएंगी।

मेरा उत्तराधिकारी चीन नहीं तिब्बती परंपराएं तय करेंगी', धर्मगुरु दलाई लामा का बड़ा बयान

नईदिल्ली,एजेंसी। तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मृत्यु के बाद अगला दलाई लामा तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार चुना जाएगा, और इस प्रक्रिया में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। दलाई लामा ने यह भी बताया कि उत्तराधिकारी की पहचान और मान्यता की जिम्मेदारी उन्होंने अपने आधिकारिक ट्रस्ट %गादेन फोडरंग ट्रस्ट' को सौंपी है। उन्होंने यह बयान एक आधिकारिक वक्तव्य के ज़रिए जारी किया।

दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी संस्था, यानी %दलाई लामा का संस्थान', भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने 2011 में किए गए उस वादे की याद दिलाई, जब उन्होंने कहा था कि 90 वर्ष के उम्र के करीब पहुंचने पर वे तिब्बती धर्मगुरुओं और जनता से विचार-विमर्श कर तय करेंगे कि इस परंपरा को जारी रखना है या नहीं।

अब जब वे 6 जुलाई 2025 को 90 वर्ष के हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीते 14 वर्षों में उन्हें तिब्बती बौद्ध नेताओं, तिब्बती संसद, केंद्र सरकार (धर्मशाला स्थित), हिमालयी क्षेत्रों, मंगोलिया, रूस और यहां तक कि तिब्बत के भीतर से भी लगातार यह अनुरोध मिला है कि यह परंपरा जारी रहनी चाहिए। इन्हीं अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए दलाई लामा ने औपचारिक रूप से घोषणा की, मैं घोषित करता हूं कि दलाई लामा की परंपरा जारी रहेगी।

दलाई लामा ने दोहराया कि अगले दलाई लामा की पहचान और मान्यता का अधिकार केवल %गादेन फोडरंग ट्रस्ट' को होगा। उन्होंने बिना नाम लिए चीन के हस्तक्षेप की संभावना को खारिज किया और कहा कि कोई भी सरकार या संस्था इस प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि अगला दलाई लामा तिब्बती परंपरा के अनुसार चुना जाएगा, जिसमें तिब्बती बौद्ध परंपराओं के वरिष्ठ लामा और धर्म रक्षक शामिल होंगे।

अपनी हालिया पुस्तक (मार्च 2025) में दलाई लामा ने लिखा है कि उनका अगला जन्म (पुनर्जन्म) भारत या किसी अन्य स्वतंत्र देश में होगा, जहां तिब्बती बौद्ध धर्म स्वतंत्र रूप से फल-फूल सके।

पुनर्जन्म का उद्देश्य मेरे कार्यों को आगे बढ़ाना है। इसलिए अगला दलाई लामा स्वतंत्र दुनिया में जन्म लेगा, ताकि वह तिब्बती बौद्ध धर्म और तिब्बती जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक बन सके।

दलाई लामा के इस बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, दलाई लामा एक राजनीतिक निर्वासित हैं, जिन्हें तिब्बती लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराधिकारी का चयन चीन के कानून और परंपराओं के अनुसार होगा। चीन का दावा है कि 1793 में किंग वंश द्वारा शुरू की गई %गोल्डन अर्न' प्रक्रिया के तहत उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार चीन को है।

चीन यह संकेत देता रहा है कि दलाई लामा की मृत्यु के बाद वह खुद से एक नया (15वां) दलाई लामा घोषित कर सकता है, जिसे दुनिया मान्यता दे। लेकिन दलाई लामा पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीतिक कारणों से पैदा किए गए किसी दलाई लामा को तिब्बती लोग और बौद्ध धर्म कभी नहीं मानेंगे।

अंधविश्वास का काला जाल : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार

झालावाड़ ,एजेंसी। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे कथित तांत्रिक प्रहलाद मेहर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह तांत्रिक पैसे दोगुने करने और ऊपरी बाधा दूर करने का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाता था।

पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि 23 जून, 2025 को रायपुर थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 जून को प्रहलाद मेहर नाम का तांत्रिक जिसका रायपुर-आजमपुर रोड पर सगस महाराज मंदिर के पास आश्रम है, उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गया। प्रहलाद ने परिवार को झांसा दिया कि वह तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक से उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगा और उनकी बेटी पर आई ऊपरी बाधा को दूर कर देगा।

अंधविश्वासी परिजनों ने अपनी नाबालिग बेटी को तांत्रिक के आश्रम भेज दिया। रात भर तांत्रिक ने तंत्र-मंत्र का दिखावा किया और सभी को वहीं सुला दिया। अगली सुबह जब परिजन जागे तो तांत्रिक और उनकी बेटी दोनों गायब थे। तांत्रिक का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तत्काल रायपुर थाने में नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा और वृत्ताधिकारी वृत्त पिड़ावा सुनील कुमार के मार्गदर्शन एवं थानाधिकारी बन्नालाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नए प्रावधानों के तहत गहन अनुसंधान और आसूचना संकलन के बाद 26 जून को अपहृत नाबालिग बालिका को केकड़ी अजमेर से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया।

जांच में सामने आया कि कथित तांत्रिक प्रहलाद मेहर ने नाबालिग बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। मेडिकल बोर्ड द्वारा दुष्कर्म संबंधी मेडिकल जांच कराई गई और बालिका को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। तांत्रिक प्रहलाद मेहर पुत्र रतन लाल उम्र 41 साल निवासी ओसाव थाना रायपुर को सोमवार 30 जून को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।

आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी बन्ना लाल सहित हैड कांस्टेबल दिलीप कुमार, महेन्द्र सिंह, कांस्टेबल मुकेश गुर्जर (आसूचना अधिकारी), हनुमान चौधरी एवं महिला कांस्टेबल मंजू शामिल थी।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से मारपीट मामले में दोषी पर लगा जुर्माना

इंडिया वार्ता ब्यूरो

अल्मोड़ा। विकासखंड कार्यालय में आयोजित एक सरकारी शिविर के दौरान पंचायत सचिव के साथ गालीगलौच और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी हीरा सिंह पटवाल निवासी कोट्यूड़ा ताल चौखुटिया को राजेन्द्र कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दंडित किया है। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 के तहत 2500 रुपये और धारा 352 के तहत 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे क्रमशः एक और दो महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला 26 जुलाई 2024 का है, जब चौखुटिया ब्लॉक कार्यालय में आयोजित एक शिविर में आरोपी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुबोध कांडपाल पर ब्लॉक प्रमुख के नाम से एक प्रस्ताव जबरन दर्ज कराने का दबाव डाला। जब सचिव ने प्रक्रिया का हवाला देते हुए प्रस्ताव दर्ज करने से मना किया, तो आरोपी गालीगलौच पर उतर आया और धमकी देने लगा। घटना की जानकारी सचिव ने अन्य ग्राम पंचायत अधिकारियों को दी, जिन्होंने बताया कि आरोपी पूर्व में भी इसी तरह से अधिकारियों को धमका चुका है। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 और 352 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान कुल 9 गवाह पेश किए गए। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार आर्य की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

सरस्वती विहार में पानी सीवर की समस्या को लेकर जल संस्थान कार्यालय का घेराव

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । । सरस्वती विहार विकास समिति अजबपुर खुर्द ने पानी और सीवर की समस्याओं को लेकर बुधवार को जल संस्थान के सरस्वती विहार स्थित सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। सरस्वती विहार विकास समिति के अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, सचिव गजेंद्र भंडारी ने कहा कि सरस्वती विहार दून की सबसे बड़ी कॉलोनी है। जहां पानी और सीवर की समस्याएं आए दिन बनी रहती हैं। अभी मानसून शुरु ही हो रहा है, लेकिन अभी से सरस्वती विहार के ब्लॉक बी वन, ब्लॉक सी, ब्लॉक ई में जगह-जगह सीवर चोक हो रही है। मानसून पूर्व तैयारियों में जल संस्थान द्वारा सीवर लाइन की सफाई व्यवस्था नहीं की गई। जिसके फलस्वरुप लोगों को यह दिन देखना पड़ रहा है। बहुत से लोगों के घरों में सीवर का पानी अंडरग्राउंड वॉटर टैंक में चला गया है। जिससे उनको सामने साफ पानी का संकट हो गया है। समिति पदाधिकारी ने क्षेत्र के लोगों के सम्मुख जल संस्थान के सहायक अभियंता मनोज बिष्ट, कनिष्ठ अभियंता रविंद्र चिनालिया को स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जल्द ही कॉलोनी की सीवर समस्याएं ठीक नहीं होगी तो विभाग की तालाबंदी की जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी। क्षेत्रीय पार्षद सोहन रौतेला ने भी अपनी नाराजगी जताई। सहायक अभियंता मनोज बिष्ट ने प्रतिनिधिमंडल के सम्मुख सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएस चौहान, उपाध्यक्ष कैलाश राम तिवारी, वरिष्ठ मंत्री अनूप सिंह फर्तियाल, मंगल सिंह कुटी, त्रिमूर्ति सिंह नेगी, सीएम पुरोहित, मूर्ति राम बिजलवाण, दिनेश जुयाल, पुष्कर सिंह नेगी, रणजीत सिंह बिष्ट, मनोज तालियान, सत्य सिंह बिष्ट, केपी जोशी, केएस कोटल, बग्वालिया सिंह रावत, युद्धवीर सिंह, यूडी उनियाल, लालमणि जखमोला, सुभाष जखमोला, लक्ष्मी रावत, रीना रावत उपस्थित थे।

SSP अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी

स्पोर्टस बाईक से स्मैक तस्करी कर रहे युवक को एसओजी व सोमेश्वर पुलिस टीम ने कल शाम कोसी से धर दबोचा

सवा तीन लाख कीमत की 10.78 ग्राम अवैध स्मैक (हेरोइन) बरामद

अल्मोड़ा (इंडिया वार्ता ब्यूरो)। श्री देवेन्द्र पींचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाकर जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं॰ हृ्रुस्न/स्ह्तत टीम को नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश पर लगातार नशा तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है। दिनांक 01.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा श्री हरबन्स सिंह व सीओ अल्मोड़ा श्री गोपाल दत्त जोशी के पर्यवेक्षण में प्रभारी एसओजी निरीक्षक श्री भुवन जोशी व थानाध्यक्ष सोमेश्वर श्री कश्मीर सिंह के नेतृत्व में एसओजी व थाना सोमेश्वर की सयुंक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रानीखेत तिराहा कोसी के पास च01ष्ट-1424 चञ्जरूको रोककर चेक किया गया तो चालक रविन्द्र बिष्ट के कब्जे से 10.78 ग्राम अवैध स्मैक (हेरोइन) बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना सोमेश्वर में मु0अ0स0- 19/2025 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।बाईक को सीज किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

रविन्द्र बिष्ट उम्र-29 वर्ष पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम स्यूना ज्योली राजस्व क्षेत्र अल्मोड़ा ।

बरामदगी- 10.78 ग्राम अवैध स्मैक (हेरोइन)

कीमत- 3,23,400/- रुपये

पुलिस टीम-

1. अपर उ0नि0 श्री प्रेम सिंह खोलिया,थाना सोमेश्वर
2. हेड कानि0 श्री प्रेम कुमार,थाना सोमेश्वर
3. कानि0 श्री वेद प्रकाश,थाना सोमेश्वर
4. कानि0 श्री राजेश भट्ट एसओजी अल्मोड़ा
5. कानि श्री राकेश भट्ट एसओजी अल्मोड़ा
6. कानि0 श्री इरशाद उल्ला एसओजी अल्मोड़ा

कुड़ी अंजानी सॉन्ग ने परखी मेरी एक्टिंग स्किल : जारा यास्मिन

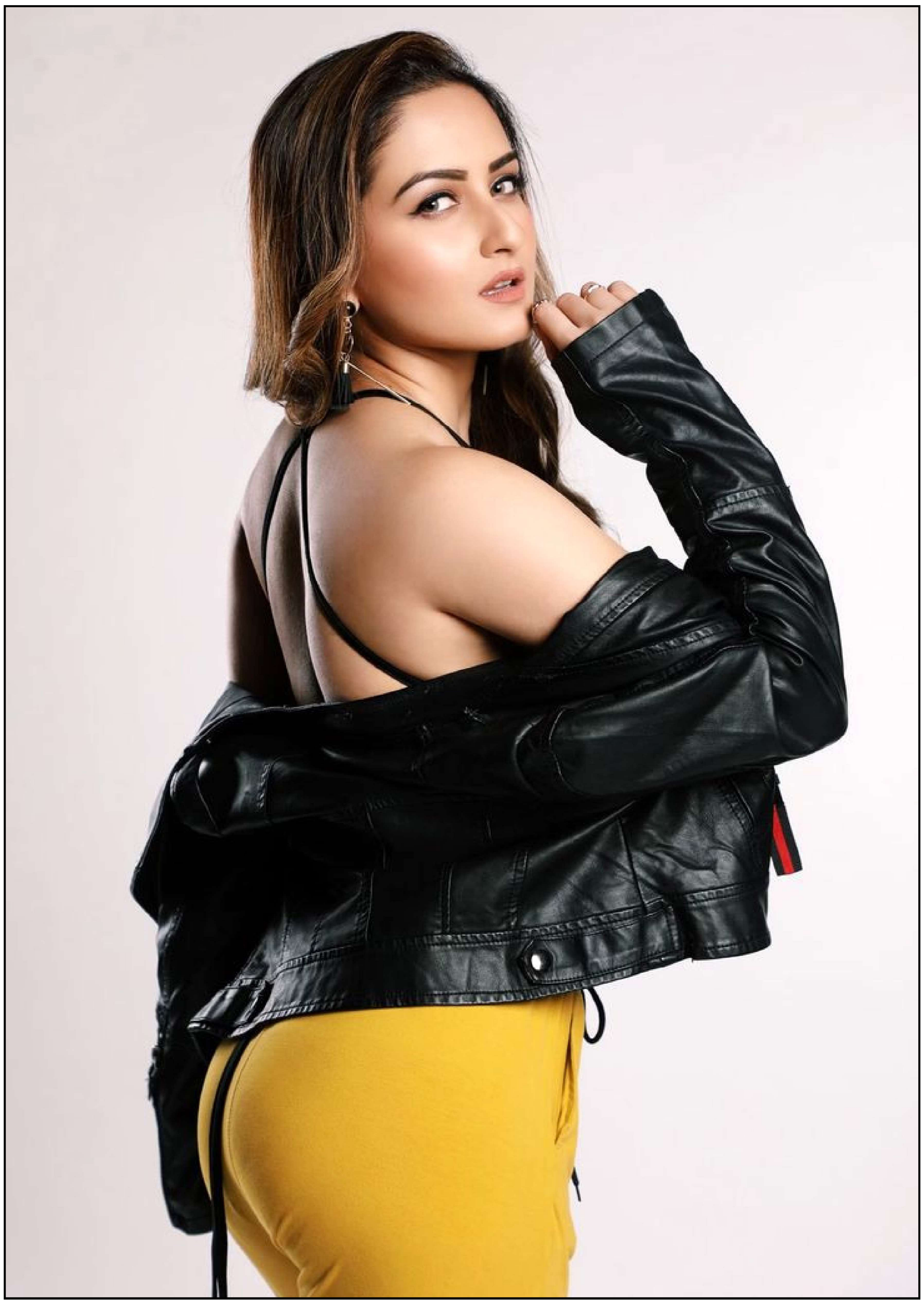

एक्ट्रेस जारा यास्मिन के हालिया रिलीज सॉन्ग कुड़ी अंजानी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। उत्साहित एक्ट्रेस ने बताया कि इस गाने ने उनके एक्टिंग स्किल को न केवल परखने का काम किया, बल्कि इससे काफी कुछ सीखने को मिला।

गाने में जारा भोजपुरी स्टार नीलकमल सिंह के साथ नजर आईं।

जारा ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करने की वजह बताते हुए कहा, सबसे पहले इस गाने की धुन ने मुझे प्रभावित किया। नीलकमल की आवाज के साथ देसी टच ने इसे एक शानदार डांस नंबर बना दिया।

कई म्यूजिक वीडियो का हिस्सा रह चुकीं जारा के लिए कुड़ी अंजानी ने उनकी अभिनय कला को परखने का काम किया।

उन्होंने बताया, मैंने कई तरह के गाने किए, सभी अलग-अलग अंदाज में... इस गाने में मुझे डांस से ज्यादा अपनी अभिनय क्षमता, एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से पेश करने की चुनौती दी।

जारा ने साझा किया कि इस गाने के लिए उनका लुक देसी और ग्लैमरस का मिक्सअप था, जिसे बनाना वास्तव में काफी चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने बताया, सेट पर इस गाने की शूटिंग मजेदार रही। इसके बीट्स और सेटअप ने इसे और भी खास बना दिया।

इस प्रोजेक्ट से जारा को काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया, कुड़ी अंजानी ने मुझे कई कॉन्सेप्ट्स और डांस फॉर्म्स में अपने टैलेंट को दिखाने का मौका दिया। यह मेरे एक्टिंग करियर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा है।

कुड़ी अंजानी के जरिए जारा ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकार नीलकमल सिंह के साथ पहली बार काम किया है। जारा ने कहा, मुझे सुष्मिता सेन के पुराने और प्रभावशाली एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना था और उसे अपने अंदाज में और भी बेहतर करना था, को-एक्टर्स का इसमें काफी सहयोग मिला।

जारा ने गाने की खासियत को लेकर कहा, इस गाने की रचना, हिंदी और भोजपुरी का मिश्रण, मजेदार एक्सप्रेशन और कोरियोग्राफी इसे और भी खास बनाता है।

यूनियनों की सदस्यता लेने पर रोक के आदेश से रोडवेज कर्मचारी खफा

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने रोडवेज में सक्रिय कर्मचारी संगठन और यूनियनों की सदस्यता में उपाधिकारी और अधिकारियों के शामिल होने पर रोक लगाने के आदेश का विरोध किया। यूनियन इसे कर्मचारियों के अधिकारों का हनन बताते हुए आदेश रद करने की मांग उठाई है। प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि रोडवेज प्रबंधन ने 14 विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को यूनियन और संगठनों की सदस्यता ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाया है। इस बारे में विधि विशेषज्ञों की राय ली गई। इसमें पता चला है कि कार्मिक ट्रेड यूनियन में किसी भी प्राविधान के अंतर्गत यूनियन की सदस्यता लेने से वंचित नहीं किए जा सकते हैं, मुख्यालय का यह आदेश विधि विपरीत है। प्रबंधन कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन इसका विरोध करती है। उन्होंने तत्काल यह आदेश वापस लेने की मांग की है।

कैबिनेट मंत्री जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सीवर और पेयजल मुद्दों पर की उच्चस्तरीय बैठक

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही सीवर और पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित और स्थायी समाधान के लिए अपने कैंप कार्यालय में जल निगम और जल संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट, मौजूदा सीवर लाइनों की जर्जर स्थिति और पुरानी पड़ चुकी प्रणालियों के व्यापक जीर्णोद्धार पर रहा। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी नई और प्रस्तावित योजनाएं दूरगामी परिणामों वाली हों, ताकि भविष्य में क्षेत्रवासियों को ऐसी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। बैठक के दौरान, मंत्री ने विशेष रूप से दून विहार में बार-बार क्षतिग्रस्त होने वाली पुरानी सीवर लाइन की समस्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पुरानी लाइन के स्थान पर नई सीवर लाइन बिछाने के लिए एक विस्तृत अनुमान (एस्टीमेट) तत्काल तैयार कर शासन को भेजा जाए। इसके अतिरिक्त, जोशी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जहां कहीं भी सीवर लाइनों में रुकावट, ओवरफ्लो या पैच रिपेयर की आवश्यकता हो, वहां तुरंत टीमों को भेजकर सुधार कार्य शुरू किया जाए। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को प्रस्तावित सीवर योजनाओं को अविलंब शुरू करने और उन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन समस्याओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और उनके स्थायी निवारण के लिए हर संभव स्तर पर सक्रिय प्रयास कर रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय सिंह, जल निगम के अधिशासी अभियंता दीपक नौटियाल, पूर्व पार्षद संजय नौटियाल सहित कई क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्ति और निवासी उपस्थित रहे। इस बैठक से क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि उनकी दीर्घकालिक समस्याओं का अब ठोस और स्थायी समाधान निकल सकेगा।

भाजपा ने प्रतिष्ठानों की जानकारी लिखने का किया स्वागत, बताया कानून सम्मत

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । भाजपा ने कांवड़ यात्रा में सुरक्षा दृष्टि से दुकान से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को कानून सम्मत बताते हुए स्वागत किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा, कांवड़ जैसी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की पवित्रता और कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार और हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं सपा सांसद हसन और कांग्रेस नेताओं के बयान को तुष्टिकरण से प्रेरित बताया। कहा, देवभूमि की जनता को यह स्वीकार नहीं हैं, उसने सपा को राज्य से पूरी तरह साफ किया है और इसी लीक पर चलने वाली कांग्रेस भी शीघ्र सपा चट होने की तरफ अग्रसर है। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने अपने नए कार्यकाल को लेकर कहा, केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास मुझ पर किया है उसपर में पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अब हम सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता और सामूहिकता से संगठन की मजबूती के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के कामों को जन जन के बीच पहुंचाना है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी हैं और पार्टी की तरफ से जिला पंचायत सदस्य पदों को लेकर समर्थित प्रत्याशियों के नामों पर विचार अंतिम चरण में है। जिसके सभी नामों की घोषणा 5 जुलाई से पूर्व चरणबद्ध तरीके से कर दी जाएगी। वहीं आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति पर भी पार्टी, शीघ्र कार्य प्रारंभ करने जा रही है। वहीं उन्होंने कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के दुकानों पर नेम प्लेट सहित सभी जरूरी जानकारी लिखने की प्रक्रिया का स्वागत किया है। कहा, कानून भी इसकी इजाजत देता है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, पंजीकरण आदि तमाम आवश्यक जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। इससे अनावश्यक रूप से कांवड़ियों और दुकानदारों के मध्य पैदा होने वाले विवादों से बचा जा सकेगा। दरअसल कांवड़ एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है, उसकी पवित्रता और कानून व्यवस्था बरकरार रखना सरकार और हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यूपी के सपा सांसद एस टी हसन द्वारा सरकार की इस कोशिश को पहलगाम के आतंकवादियों से जोड़ने का कठोर शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा, सपा तुष्टिकरण की राजनीति के लिए इस तरह के बयान जानबूझकर देती है।

देहरादून में मुख्य सचिव ने जारी किए अहम निर्देश: ई डीपीआर, ई-ऑफिस और बायोमेट्रिक पर जोर

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में राज्य और जनहित से जुड़ी योजनाओं के साथ-साथ सरकारी कर्मियों की समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य विभागों के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता लाना है।

ई-डीपीआर मॉड्यूल को अनिवार्य बनाने का निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने विभागों के तहत होने वाले कार्यों के लिए %ई-डीपीआर मॉड्यूल% को पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने से लेकर सरकार तक पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया ई-डीपीआर के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग शत-प्रतिशत ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया है।

कर्मचारियों के सर्विस बुक डेटा को अपडेट करने पर बल

मुख्य सचिव ने यूकेपीएफएमएस (उत्तराखंड पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से सभी कर्मियों के सर्विस बुक डेटा को अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईएफएमएस (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) डेटा के शीघ्र डिजिटलीकरण और इसके मैकेनिज्म को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सभी विभागाध्यक्षों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और वाहन चालकों के जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) संबंधी डेटा को भी लगातार अपडेट रखने के निर्देश दिए गए हैं।

ई-ऑफिस और बायोमेट्रिक उपस्थिति को शत-प्रतिशत लागू करने का दोहराया निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने-अपने विभागों में शत-प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली को शीघ्र लागू करने के अपने पहले के निर्देशों को दोहराया। उन्होंने जनपद स्तरीय कार्यालयों को भी जल्द से जल्द ई-ऑफिस पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, विभागों में शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

जिलाधिकारियों के साथ वीसी का समय निर्धारित, शुक्रवार सायंकाल होगा आयोजन

विभिन्न विभागों द्वारा जिलाधिकारियों को अलग-अलग समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनावश्यक रूप से व्यस्त रखने की समस्या को देखते हुए मुख्य सचिव ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवल प्रत्येक शुक्रवार सायंकाल को ही आयोजित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जिन भी विभागों को जिलाधिकारियों के साथ बैठक करनी है, वे इस निर्धारित समय पर अपनी बात रख सकेंगे। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि बैठकों के एजेंडा पॉइंट्स जिलाधिकारियों को पूर्व में ही साझा किए जाएं।

आईएएस अधिकारियों को प्रथम नियुक्ति के कार्यस्थलों को गोद लेने में तेजी लाने का निर्देश

मुख्य सचिव ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अपनी प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियुक्ति के कार्यक्षेत्रों (विकासखंड, तहसील और जिला मुख्यालय) को गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने विभागों के तहत केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की लगातार समीक्षा करने पर भी बल दिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री नितेश कुमार झा, श्रीमती राधिका झा, श्री सचिन कुर्वे, श्री दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, श्री चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. नीरज खैरवाल, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी, डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री रणवीर सिंह चौहान एवं धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रथम पृष्ठ का शेष 26 किमी रिस्पना - बिंदाल एलिवेटेड...

को इस अद्वितीय फोटोग्राफी संकलन द्वारा साकार रूप दिया है। भूमेश जी केवल एक फोटोग्राफर नहीं हैं बल्कि वे एक ऐसे कलाकार हैं, जो प्रकृति के सौंदर्य को आत्मा की गहराई से अनुभव करके अपने कैमरे के माध्यम से दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कॉफी टेबल बुक जो भी देखेगा, वो न केवल उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता से अभिभूत होगा, बल्कि उसे देखने के लिए उत्तराखंड की ओर खींचा चला आएगा।

नई पर्यटन नीति से डेस्टिनेशन उत्तराखंड स्थापित होगा वैश्विक पर्यटन मानचित्र -मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति के अंतर्गत निवेशकों को आकर्षित करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की है।

राज्य में दो स्पर्चुअल जोन हो रहे तैयार- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में धार्मिक, साहसिक, ईको-टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। आज जहां एक ओर केदारखंड की भांति मानसखंड कॉरिडोर को भव्य रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश और हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध रूप से कार्य भी किया जा रहा है। इस वर्ष से हमने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है जिसको प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों हर्षिल- मुखबा के दौरे पर आए थे। हम राज्य में साहसिक पर्यटन जैसे ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है।

उत्तराखंड बना मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में फिल्म शूटिंग को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी प्रारंभ किया है।साथ ही हम उत्तराखंड में शूटिंग करने पर फिल्म निर्माताओं को विशेष सब्सिडी और अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड देश-विदेश के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हमारे चार गांवों जखोल, हर्षिल, गुंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री श्री बंशीधर तिवारी, वीसी दून विश्वविद्यालय श्रीमती सुरेखा डंगवाल, वरिष्ठ पत्रकार श्री सतीश शर्मा, प्रदेशभर से आए फोटोजर्नलिस्ट मौजूद रहें।

सैन्यधाम का निरीक्षण करते सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून स्थित गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सैन्यधाम के अंतिम चरण के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा जाए।

सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्यधाम, जो उत्तराखंड की वीरभूमि की भावना और शहीदों के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण मंत्री के रूप में मुझे इस पवित्र कार्य से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के समाप्त होते ही जल्द तिथि तय कर यह सैन्य धाम प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस भव्य सैन्य धाम में उत्तराखंड के शहीदों के आंगन की मिट्टी तथा गंगा, यमुना सहित कई पवित्र नदियों के जल का समावेश किया गया है, जो इस स्थल को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है।

सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने यह भी बताया कि देशभर के प्रमुख सैन्य स्मारकों का गहन अध्ययन करने के बाद सैन्यधाम की डिज़ाइन तैयार की गई है, जिससे यह न केवल एक स्मारक बल्कि शौर्य, बलिदान और गौरव की प्रतीक स्थली के रूप में विकसित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ यहां आकर अपने शहीदों के बलिदान का गर्व से स्मरण कर सकें। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि जिस प्रकार श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन हेतु आते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग सैन्यधाम में भी आएंगे और शहीदों को नमन करेंगे। निरीक्षण के दौरान सैन्यधाम की उच्च स्तरीय समिति के सदस्य मेजर जनरल (सेनि) सम्मी सभरवाल, सैनिक कल्याण निदेशक ब्रिगेडियर (सेनि) अमृतलाल, एमडी उपनल के प्रबंध निदेशक बिग्रेडियर (सेनि) जेएनएस बिष्ट, सैनिक कल्याण विभाग के अपर सचिव श्याम सिंह सहित सैनिक कल्याण एवं पेयजल निगम के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक संदीप शर्मा ने इंडिया प्रिन्टर शांप न. 06 संगम प्लाजा धर्मपुर देहरादून से मुद्रित करवाकर मोहक्कमपुर खुर्द पोस्ट आई.आई.पी. रेलवे क्रसिंग हरिद्वार रोड़ देहरादून (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।

प्रधान सम्पादक : संजीव शर्मा

संपादक: संदीप शर्मा

सह सम्पादक : डा. विष्णु बिश्वास

संजीव अग्निहोत्री गढ़वाल प्रभारी

अल्मोड़ा जिला प्रभारी : रोहित कार्की

अल्मोड़ा संवाददाता : रक्षित कार्की

ब्यूरो चीफ : राजीव अग्रवाल

Email.
indiawarta@gmail.com
indiawarta@rediffmail.com
Web Site
www.indiawarta.com
R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104
M- 7500471414,7500581414

नोट- समाचार पत्र में सभी पद अवैतानिक हैं। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा।
R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104

सूबे के नर्सिंग कॉलेजों में पूर्व की भांति रहेगी प्रवेश प्रक्रिया

विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया निर्णय

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर के राजकीय एवं निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया इस बार भी पूर्व की भांति आयोजित की जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही एच.एन.बी. चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है जो भविष्य में नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के लिये आईएनसी गाइडलाइन के अनुरूप ठोस प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपेगी।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज दून मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर बैठक का आयोजन किया गया जिसमे चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन, निजी नर्सिंग कॉलेज एसोशिएसन के पदाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जिसमें विभागीय मंत्री ने नर्सिंग पाठ्यक्रमों में अभी तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू न किये जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन व शासन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुये विश्वविद्यालय प्रशासन व शासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि छात्रों के भविष्य के लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में नर्सिंग कॉलेज के एसोशिएसन के पदाधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुये कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के तहत निजी कॉलेजों की 50 फीसदी सीटें भी भर पाना संभव नहीं है। लिहाजा पूर्व की भांति 50 फीसदी सीटें निजी संस्थान संचालकों को एसोसिएशन के माध्यम से भरने की अनुमति दे दी जाय। शेष 50 फीसदी सीटें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवंटित की जाय। इसके बावजूद रिक्त रहने वाली सीटों को भरने की अनुमति भी एसोसिएशन को दी जाय। जिस पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ओकांर सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के उपरांत तीन काउंसिलिंग के उपरांत भी रिक्त रहने वाली सीटों को निजी संस्थान न्यूनतम अर्ह शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्वयं भर सकते हैं यह व्यवस्था नर्सिंग पाठ्यक्रम के अधिनियम में विद्यमान है। दोनों पक्षों को सुनने बाद विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया कि समय की बाद्धता को देखते हुये इस बार भी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्व की भांति आयोजित की जाय ताकि समय रहते सरकार एवं निजी नर्सिंग कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जा सके। जबकि अगले शैक्षणिक सत्र के लिये नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी व सुलभ बनाया जायेगा, जिसके लिये मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें दो सदस्य निजी नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन के भी शामिल किये जायेंगे। समिति की रिपोर्ट व आईएनसी की गाइडलाइन के आधार पर शासन प्रवेश प्रक्रिया के लिये अपने स्तर से नई गाइडलाइन जारी करेगा।

बैठक में सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार, एच.एन.बी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, कुलसचिव मेडिकल विश्वविद्यालय डॉ. आशीष उनियाल, राजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल मनीषा ध्यानी, निजी नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन के पदाधिकारी व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

गुण्डा एक्ट के तहत दो अपराधी किए जिलाबदर

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। जिला मजिस्ट्रेट देहरादून सविन बसंल ने आपराधिक मामलों में संलिप्त दो लोगों के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कडी कार्रवाई करते हुए जिले से दरबदर कर दिया है। यह कार्रवाई सुनील यादव उर्फ सन्नी पुत्र दिलीप यादव निवासी मंगल बस्ती राजीव नगर थाना नेहरू कालोनी देहरादून और मौहम्मद रजा उर्फ भूरा पुत्र मोबीन निवासी जैन प्लॉट वाणी विहार भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला थाना रायपुर देहरादून के विरूद्ध की गई है। आपराधिक मामलों में संलिप्त इन दोनों को गुण्डा घोषित करते हुए 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए है। साथ ही इन दोनों को जनपद से बाहर रहने पर अपने निवास स्थान का पूरा पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराना भी आवश्यक किया गया है। धारा 3,4,5 या 6 के अधीन पारित आदेशों का उल्लंघन करने पर कठोर कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकता है परंतु 06 माह से कम नही होगा, के दण्ड और जुर्माना दोनों का भी भागी होगा। आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कर 24 घंटे के अंदर जनपद छोड़ने और इसकी अनुपालन आख्या न्यायालय को उपलब्ध कराने के भी आदेश जारी किए गए है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून में दाखिल वाद सरकार बनाम मौहम्मद रजा उर्फ भूरा मामले में थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट में मौहम्मद रजा उर्फ भूरा को शातिर अपराधी बताया है। जो पूर्व में थाना डालनवाला क्षेत्र में स्थित राजकीय कोरोनेशन जिला चिकित्सालय परिसर में चिकित्सालय स्टॉफ पर हमला करने, लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौच व सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में संलिप्त रह चुका है। विगत वर्ष 2023 में थाना क्षेत्रान्तर्गत अपराधिक घटना को अंजाम दे चुका है। वर्तमान समय में जमानत पर है और वर्तमान समय में भी अपराधिक कृत्यों में सक्रिय है। विपक्षी के विरूद्ध थाना डालनवाला में पूर्व में दो अभियोग पंजीकृत है। थानाध्यक्ष थाना रायपुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और विपक्षी को आपत्ति प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विवेचना एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के आधार पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने मौहम्मद रजा उर्फ भूरा पुत्र मोबीन निवासी जैन प्लॉट वाणी विहार भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला थाना रायपुर देहरादून को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में गुण्डा घोषित करते हुए 06 माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए है।

वहीं सरकार बनाम सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की मामले में थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट में सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की को शातिर अपराधी बताया है। जो थाना क्षेत्रान्तर्गत लूटपाट करने, अवैध रूप से शस्त्र रखने का अभ्यस्त है। पूर्व में अपराधों में संलिप्त है और वर्तमान में जमानत पर है। जिससे आम जनता में भय का माहौल है। विपक्षी को नोटिस की तामीली किस्म दोयम अमल में लायी गई है। विपक्षी नियम तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। और नही विपक्षी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विवेचना एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के आधार पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने सुनील यादव उर्फ सन्नी पुत्र दिलीप यादव निवासी मंगल बस्ती राजीव नगर थाना नेहरू कालोनी देहरादून को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में गुण्डा घोषित करते हुए 06 माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए है।

पाठको के लिए

मान्यवर पाठकगण

१. दैनिक इंडिया वार्ता समाचार पत्र हेतु अपने व्यक्तिगत या संस्थान की ओर से प्रकाशनार्थ लेख/समस्याएं व समाचार हमें भेजे व प्रति दिन नियमित रूप से समाचार पत्र प्राप्त करने को कार्यालय से सम्पर्क करे।

२. समाचार पत्र के बारे में आप के विचार व सुझाव आमंत्रित है।

३. नियमित पाठक बनने के लिए आपके द्वारा समाचार पत्र की सदस्यता ग्रहण करना प्रार्थनीय है।

४. व्यक्तिगत एवं व्यापारिक संस्थानो के तथा अन्य विज्ञापन आमंत्रित है।

सम्पादक
दैनिक इंडिया वार्ता

कार्यालय : मोहकमपुर खुर्द नियर आई आई पी हरिद्वार रोड देहरादून।
दूरभाष: 7500581414,9359555222

कांवड़ियों से भरे ट्रक के पलटने से 3 लोगों की मौत, 14 गंभीर रूप से घायल

नई टिहरी,इंडिया वार्ता ब्यूरो। कांवडियों को ऋषिकेश से गंगोत्री ले जा रहा एक ट्रक टिहरी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। जिसके नीचे दबकर तीन की मौत हो गयी। वहीं 14 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह एक ट्रक कांवड़ियों को लेकर ऋषिकेश से गंगोत्री की ओर जा रहा था। ट्रक में 18 से 20 कांवड़िए सवार थे। इसी दौरान टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाजल फकोट के बीच अचानक ड्राइवर ट्रक पर से संतुलन खो बैठा। इस दौरान अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क किनारे खाई की ओर पर पलट गया। संयोग से ट्रक ऊपर ही अटक गया। ट्रक के पलटते ही वहां चीखपुकार मच गई। हादसे की खबर लगते ही स्थानीय लोग दुर्घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। इस बीच किसी ने पुलिस और एसडीआरएफ को भी हादसा होने की सुचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई। ट्रक पलटने से उसमें सवार ज्यादातर कांवड़िए ट्रक के नीचे दब गए। टिहरी एसपी के अनुसार ट्रक में 18 से 20 कांवड़िए सवार थे। राहत और बचाव टीम ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया। जेसीबी से ट्रक को सीधा किया गया। इस दुर्घटना में 17 कांवड़ियों को रेस्क्यू किया गया। इनमें से 3 की मौत हो गई है। 14 घायल हुए हैं। घायलों को एंबुलेंस से नरेंद्र नगर स्वास्थ्य केंद्र फोकट भेजा गया है। घायल कई कांवड़ियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायल कांवड़ियों में से 5 को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। 9 कांवड़िए नरेंद्र नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। टिहरी गढ़वाल एसपी के अनुसार ट्रक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आया था।